

ऊर्जा संरक्षण संहिता पर कार्यशाला

पटना. ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिसियेंसी ने ऊर्जा संरक्षण संहिता विकसित किया है. इसीबीसी वाणिज्यिक भवन में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के लिए गाइडलाइन तय करता है. बिहार रिन्यूअल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा राज्य की भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से इसीबीसी में बदलाव लाकर इसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया में लगा है. ब्रेडा ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिसियेंसी के साथ मिलकर विद्युत भवन में गुरुवार को एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया.

आज

कोलकाता, 19.01.2018

बिहार में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अपनाने की प्रक्रिया में

पटना (आससे)। ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसियेंसी (बीईई) विद्युत मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय भरत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण संहिता (इसीबीसी) विकसित किया है। इसीबीसी वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए एक गाइडलाइन है।

बिहार रिन्यूअल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसियेंसी (बीईई) और यूरोपियन यूनियन (ई.यू.) का एकटिव सहायता प्राप्त है।

ई.यू. की मदद के साथ चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में इसीबीसी कोषांग की स्थापना की गयी है। इसीबीसी को अनिवार्य किये जाने से राज्य को वाणिज्यिक भवन में ऊर्जा की खपत कम करने में तथा कम कार्बन वृद्धि के बढ़ावे में मदद मिलेगी। इसीबीसी भवन निर्माताओं, डिजाइनर तथा एंक्वैक्टर को ऊर्जा संरक्षित भवन बनाने के लिए कुछ मानदेय तय करता है तथा भवन की डिजाइन में रिन्यूअल इनर्जी सोर्सिंग का भी विकास करेगा। इस कोर्ड का उद्देश्य ऊर्जा की बचत को बढ़ाना तथा वाशिंगटो के लिए सुविधा प्रदान करना है। यह आशा की जाती है कि इसीबीसी के अपनाने से पारंपरिक भवनों की तुलना में ३०-४० प्रतिशत ऊर्जा की बचत होगी।

बिजली बचाने की संहिता अपनाएगा

पटना। सूचे में बन चुके या बनने वाले भवनों में बिजली बचाने के लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई संहिता को अपनाने की प्रक्रिया में है। ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसियेंसी के तहत बनाए गए ऊर्जा संरक्षण संहिता में ऊर्जा दक्षता और तय गाइडलाइन पर अमल करने की कवायद शुरू हो गई है।

गुरुवार को कार्यशाला में बिहार रिन्यूअबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) के निदेशक आर. लक्ष्मणन ने कहा कि राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के सलाहकार प्रो. रंजन रावल ने इसीबीसी की डिजाइन पर ही भवन का डिजाइन तैयार करने को कहा। उप निदेशक खुशींद अनवर सिद्धीकी ने नालंदा के एक गांव में चल रहे मॉडल इनर्जी इफिसियेंट परियोजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में सौरभ, राजीव, शमी नूर, रंजन के पांडे आदि मौजूद थे।

The Telegraph India

Friday, January 19, 2018

Code for greener buildings

Sanjeev Kumar Verma Jan 19, 2018 00:00 IST



BREDA director R Lakshmanan (centre) at a workshop-cum-training programme on Thursday. Telegraph picture

Patna: The Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) has formulated an energy conservation building code for the state which would come into force after approval of the state government.

The agency has made this document, which has been sent for technical vetting of the bureau of energy efficiency (BEE), a statutory body under the Union ministry of power, after making necessary changes in the energy conservation building code (ECBC) formulated by the BEE in accordance with the geographical requirements of Bihar. The BEE has given powers to the states to modify the energy conservation code as per their geographical requirements.

"After approval of the BEE, the document would be sent for the approval of the state government and once this approval would be procured the ECBC would come into effect in the state," BREDA director R Lakshmanan said on Thursday.

The ECBC is a guideline for energy efficiency and energy conservation for commercial buildings. The code is applicable to all new (to be constructed) commercial buildings having connected load of 100kw or more.

The adoption of the ECBC will help reduce commercial buildings' energy consumption and promote low-carbon growth. The ECBC sets parameters for builders, designers and architects towards energy efficient buildings and also to integrate renewable energy sources in building design. It is expected that adoption of the ECBC will save 30-40 per cent of energy in comparison to conventional buildings.

In a bid to make the stakeholders aware of the energy conservation code, BREDA on Thursday organised a workshop-cum-training programme in association with the BEE. It was attended by officials from building construction department, police building construction department, planning department, urban development & housing department, South Bihar Power Distribution Company Limited, North Bihar Power Distribution Company Limited, Patna Municipal Corporation and the municipal corporations of Munger and Nalanda.

Lakshmanan briefed participants about the importance of the ECBC and urged them to generate awareness about it among the stakeholders.